आईआईडीसी की अध्यक्षता में टेक्सटाइल और अपेरल पार्कों के प्रस्तावों की स्क्रीनिंग

प्रदेश में सात स्थानों पर बनेंगे 50 से 100 एकड़ के पार्क

प्रत्येक पार्क में लगेंगी 50 से 100 इकाइयां

लखनऊ। प्रदेश को गारमेंट का हब बनाने के लिए इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एवं अपेरल पार्कों की स्थापना की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश में सात स्थानों पर इन पार्कों की स्थापना के लिए निवेशकों के प्रस्ताव मिले हैं। ये पार्क 50 से 100 एकड़ में स्थापित होंगे। हर पार्क में 50 से 100 इकाइयां होंगी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) की अध्यक्षता वाली कमेटी पार्क के लिए निवेशकों के प्रस्तावों की स्क्रीनिंग कर उसे अनुमोदित करेगी।

दरअसल, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एवं अपेरल पार्कों के विकास के लिए राज्य सरकार ने निवेशकों के प्रस्तावों की स्क्रीनिंग के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया था। पूर्व में जारी आदेश में यह स्पष्ट नहीं था कि कमेटी किसकी अध्यक्षता में होगी। अब इसमें आंशिक संशोधन करके आईआईडीसी जोड़ दिया गया है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार ई-दस्तावेज और ई-बिड की स्क्रीनिंग के लिए गठित समिति को यथावत रखा गया है जबकि अनुमोदन के लिए बनी शासकीय स्वीकृति समिति में संशोधन करते हुए आईआईडीसी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसमें अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई, प्रमुख सचिव न्याय तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीसीडा को सदस्य नामित किया गया है।

इनके अतिरिक्त आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को समिति का संयोजक/सदस्य बनाया गया है। स्क्रीनिंग समिति निवेशकों के दस्तावेजों का परीक्षण कर स्वीकृति के लिए शासकीय समिति को अग्रसारित करेगी। शासकीय स्वीकृति समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर इच्छुक निवेशकों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति प्रदान करेगी। जरूरत पड़ने पर गठित समितियां निवेशकों को समिति की बैठक में आमंत्रित भी कर सकेंगी। ब्यूरो

इन शहरों के लिए आए प्रस्ताव

निवेशकों ने मेरठ, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, चंदौली, कानपुर व झांसी में पार्क स्थापित करने के लिए प्रस्ताव दिए हैं। अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग रमा रमण का कहना है प्रस्ताव जल्द स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्यवाही होगी।